an>

Title: Need to connect border areas by road in jammu & Kashmir and Ladakh.

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू- कश्मीर के लद्दाख इलाके में विकास के कार्यक्रम में चीन ने क्यों बाधा डाली? हाल ही में हमारे गृह राज्य मंत्री ने वहां घोषित किया था कि वहां के सभी सीमावर्ती इलाकों को सड़क से जोड़ा जाएगा जिसमें चीन की एक ऑब्जेक्शन आई थी। लेकिन जिस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह यह है कि हाल ही में जो वहां अपैक्स समिट हुआ था, जिसमें चीन के राष्ट्रपति ज़ी जिंपिंग और जापान के प्रधान मंत्री शिंजो आबे जी के बीच में समझौता हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में जापान का जो विशेष कार्यक्रम ले रहे हैं, उसमें बाधा डालें। यह जो बाधा डाली गई है, खास तौर से हमारा जो सीमा सड़क संगठन है, जिसको बीआरओ के नाम से जाना जाता है, वह जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी का था, उसमें बाधा डालने का उनका पूरा कार्यक्रम था। लेकिन अभी चूंकि चीन ने उसमें बाधा डाली है, जैसे एडीबी , वर्ल्ड बैंक , सबमें बाधा डाली है। जब महाराष्ट्र , गुजरात में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का एक अंग नहीं हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश को या लद्दाख के जो इलाके हैं, विकास के कार्यक्रम अगर आप चीन या जापान से नहीं ले सकते तो मैं हमारी सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में कदम उठाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री निनोंग इरिंग द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को एसोशिएट किया जाए।